District	Amount (Rs. in lakh)
Murshidabad	694.630
Malda	427.305
Dakshin Dinajpur	728.790
Uttar Dinajpur	495.060
Cooch Behar	563.946
Jalpaiguri	237.760
Darjeeling	108.360

ताप बिजली घरों को कोयले की कम आपूर्ति

2062. **श्री सोमपाल:** क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कोयले के कम उत्पादन और इसकी ढुलाई की समस्याओं के कारण देश के विभिन्न ताप बिजली घरों में उपलब्ध कोयले के भण्डार केवल कुछ ही दिनों के लिए पर्याप्त है; और

(ख) यदि हां, तो इन बिजली घरों में कोयले के भण्डारों की वर्तमान स्थिति क्या है और इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर): (क) देश में अप्रैल-नवम्बर, 1995 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लि० (को०इं० लि०) तथा सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि० (सि०को०कं०लि०) से विभिन्न विद्युत उपयोगिताओं को वास्तविक रूप में किए गए कोयले के प्रेषण 115.88 मिलियन टन (अनंतिम) रहा, जबकि इस अवधि के लिए लक्ष्य 116.52 मिलियन टन रखा गया था। इस संबंध में लक्ष्य की प्राप्ति 99.45% रही और विद्युत गृहों के पास कोयले का कम स्टाक होने के कारणों में, निम्नलिखित कारण शामिल हैं:—

(1) कोयले का मात्रा की तुलना में अधिक उपभोग, जोकि कोयला कंपनियों द्वारा इन विद्युत गृहों को आपूर्ति किया जाना अपेक्षित है।

(2) विद्युत गृहों के स्थलों पर कोयले के उतराई संबंधी अवरोध।

(3) विद्युत गृहों द्वारा कोयले की बिक्री की देय बकाया राशि की अदायगी न किए जाने के कारण कोयले की आपूर्ति प्रतिबंधित की जा रही है।

(4) रेलवे का संचलन संबंधी अवरोध; और

(5) सिं० को०कं०लि० में छुटपुट हड़ताल होने के कारण आपूर्ति प्रभावित हो रही है और देश के पूर्वी भागों में कुछ खानों का जलमग्न होना है।

(ख) देश में 65 विद्युत गृहों के पास कोयले का कुल स्टाक, जिस पर कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है, यह 12-12-1995 की स्थिति के अनुसार 2.947 मिलियन टन था।

कोयला कंपनियां, कोयले के उत्पादन को अधिकतम किए जाने के प्रयास कर रही हैं और ये इसकी सभी उपभोक्ताओं को आपूर्ति करती हैं, जिसमें विद्युत गृह भी शामिल है, जोकि योजना आयोग के साथ किए गए परामर्श के अनुसार वार्षिक योजना को दिए गए अंतिम रूप के अनुसार की जाती है। विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने के मामले में उच्चतम प्राथमिकता दी जाती है और इस मामले में एक अंतर-मंत्रालयीय समिति द्वारा नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है। इस बारे में जहां कहीं भी अपेक्षित होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। किन्तु, कोयले का स्वतंत्र रूप में आयात किया जा सकता है और विद्युत गृह सहमति हुए स्तर से ऊपर की मांग में हुई किसी तरह की वृद्धि को पूरा किए जाने हेतु आयातों के माध्यम से अपनी आपूर्ति की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। विद्युत का उत्पादन किए जाने का भी विकल्प अब उपलब्ध है।

Proposal for creation of separate departments of consumer affairs

2063. SHRI SARADA MOHANTY:
SHRI SATYA PRAKASH MALAVIYA:

Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) whether Government have asked the State Governments to create a

separate department of Consumer Affairs;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the reasons of the state Governments thereto; and

(d) the steps taken by Government to make the consumer movement a great success?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION (DEPTT. OF CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) (SHRI VENOD SHARMA): (a) Yes, Sir.

(b) It has been felt that creation of a separate Department of Consumer Affairs would strengthen the consumer movement in the country.

(c) The State Governments have shown concern for the consumers. All the State Governments have set up consumer redressal fora.

(d) Under the Consumer Protection Act, 1986, 3 tier redressal agencies have been set up. At present, one National Consumer Disputes Redressal Commission (National Commission). 31 State Consumer Disputes Redressal Commission (State Commission) and 457 Consumer Disputes Redressal Fora (District Fora) are functioning in the States/UTs. In addition one State Commission and two Divisional Fora are also functioning in the State of Jammu & Kashmir where they have enacted a separate Jammu & Kashmir Consumer Protection Act, 1987. The Central Government is providing one time central assistance to the State Governments/UTs for strengthening the infrastructural facilities of these State Commissions and District Fora.

Fall in production in Dankuni Coal Complex

2064. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the attention of Government has been drawn to the press news-item captioned "CIL's Dankuni Coal Complex falls by the wayside" as reported in Statesman dated 29th November, 1995;

(b) if so, the facts and details thereof;

(c) whether the Dankuni Coal Complex has failed to boost production/ exploration of Coal as targetted; and

(d) if so, the concrete measures Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI JAGDISH TYTLER): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The investment for setting up of the Dankuni Coal Complex (DCC) was approved by the Government in July 1980. Construction work for the main plant was entrusted to the Heavy Engineering Corporation (HEC), Ranchi on turn-key basis. The construction of the plant was delayed mainly due to slow execution by M/s HEC and their associates. The construction of the plant was completed in May, 1989 and the commercial operation commenced in May, 1990. Many of the teething problems observed since commissioning were rectified by Coal India Limited (CIL) as HEC failed to rectify these in time. The main reason for low utilisation of the plant is due to the failure of the linked consumer, Greater Calcutta Gas Supply Corporation (GCGSC) to draw the agreed volume of gas from the plant.

(d) In order to overcome the situation, a marketing strategy for the different products of the plant was evolved in a series meetings taken by the Ministry of